>

Title: Need to drop the proposal to give cash instead of foodgrains to BPL families and continue with the present system of distribution of foodgrains to BPL families through Public Distribution System.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): केन्द्र सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थ राज्य सरकारों के माध्यम से उपलब्ध कराती है। इस केन्द्रीय योजना से गरीब लोगों को पेट भरने के लिए अन्न प्राप्त होता है। लेकिन, अब खाद्यान्न के बदले नकद धनराशि दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है, जो तर्कसंगत नहीं है। यदि इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाता है तो गरीब लोगों को खाद्यान्न के बदले एक निश्चित राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

यह किसी से छिपा नहीं है कि यदि गरीब परिवार के मुखिया को अन्न के बदले नकद राशि वितरित की जायेगी तो बहुत संभावना है कि परिवार का मुखिया इस राशि का उपयोग परिवार के भरण-पोषण के लिए न करके अपनी निजी आवश्यकताओं में पूरा करेगा। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय धनराशि का दुरूपयोग होगा तथा एक गरीब परिवार, जो केन्द्रीय खाद्यान्न से अपना भरण-पोषण करता था, वह इस सुविधा से वंचित हो जायेगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निरस्त करे और यदि किसी कारणवश इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना जरूरी है तो फिर इस योजना को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संगठनों से सुझाव लेकर ही इस संबंध में कोई कदम उठाए जायें।